सर्वशील मागो

विरूद्ध

हरियाणा राज्य और अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 545, 2008)

<u>25 मार्च 2008</u>

**[एस.बी. सिन्हा और वी.एस. सिरपुरकर, जे.जे)**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 482 - उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां- विवाद के कारण निजी पक्षों और शिकायतकर्ता के बीच विभिन्न मुकदमे- निजी पक्ष पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को प्रतिबंधित पदार्थ रखने के लिए झूठा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं- शिकायतकर्ता पंजीकरण की मांग कर रहा है पुलिस अधिकारी और निजी पक्षों के खिलाफ आपराधिक मामले और जांच भी - उच्च न्यायालय द्वारा अपील पर इनकार:- जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराध की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए मामला बनाया गया - शिकायत डीआइजी रैंक के अधिकारी को आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया- जांच के लिए मामले को सीबीआई को भेजना आवश्यक नहीं है- दंड संहिता, 1860- एस.एस. 341, 342, 211 और 120-बी - स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985- धारा 58।

**अपीलकर्ता की बेटी की शादी प्रतिवादी संख्या 6 के बेटे के साथ हुई थी। पार्टियों के बीच विवाद था. अपीलकर्ता के प्रतिवादी संख्या 5 के साथ भी तनावपूर्ण संबंध थे। अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए, हालांकि, उन सभी को बरी कर दिया गया। आरोप है कि प्रतिवादी सं. 5 और 6 प्रतिवादी संख्या 4-पुलिस अधिकारी की मिलीभगत से, अपीलकर्ता को प्रतिबंधित दवाएं**

**रखने के आरोप में झूठा फंसाने की कोशिश की। तीन मौकों पर तलाशी ली गई लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। अपीलकर्ता उत्तरदाताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने में सफल नहीं हुआ। इसके बाद, अपीलकर्ता ने धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत एक याचिका दायर की। धारा 341, 342 और 211 आईपीसी पठित धारा 58 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पठित आईपीसी की धारा 120-बी, के तहत प्रतिवादी संख्या 4, 5 और 6 के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की।**

उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया। अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की। एसएलपी पर नोटिस जारी किए गए और सीबीआई को भी नोटिस जारी किए गए। इस न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि डीजीपी की देखरेख में डीआइजी रैंक का एक अधिकारी इस बात की स्वतंत्र जांच करेगा कि क्या प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपीलार्थी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने की कोशिश कर परेशान करना कोई प्रयास किया गया था।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया:

डीजीपी के कहने पर डीआइजी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट, जो जांच की प्रकृति की थी, को देखने के बाद यह पाया गया कि अपराध की जांच का मामला है। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत की आगे की जांच DIG रैंक के अधिकारी द्वारा निर्देशित की जाती है। हालाँकि, इस स्तर पर, मामले को सीबीआई को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि डीआईजी ने अब तक मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की है। शिकायत के आधार पर उत्तरदाताओं सहित सभी संबंधित लोगों और ऐसे अन्य लोगों के खिलाफ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाएगी जिनकी दिनांक 8.8.2004

की घटना में कोई भूमिका थी। आगे की कार्रवाई, यदि आवश्यक हो, तो ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ की जाएगी, जिनका अपीलकर्ता के उत्पीड़न में हाथ पाया गया है, जिनकी कार की लगातार तीन मौकों पर तलाशी ली गई थी, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। आवश्यकता महसूस होने पर, अपीलकर्ता को इस न्यायालय से पुनः संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है.

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की आपराधिक अपील संख्या 545

आपराधिक विविध संख्या 44156-एम/2004 में चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 9/9/2005 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

सुबोध मार्कंडेय, चित्रा मार्कंडेय और आर अग्रवाल अपीलकर्ता के लिए.

विकास सिंह, ए.एस.जी., बी.एस. मोर, नी राज मोर, महिंदर सिंह दहिया, रजनी ओहरी, बी.के. प्रसाद, पी. परमेश्वरन, कुसुम सिंह, आर.सी. कौशिक, राजीव गौड़ 'नसीम', राजेश रंजन एवं टीवी.जॉर्ज उत्तरदाताओं के लिए

**<u>न्यायालय का निर्णय सुनाया गया</u>**

**वी.एस. सिरपुरकर, जे.**

1. विशेष अनुमति स्वीकृत।

2. अपीलकर्ता ने यहां उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत धारा 482 सीआर के तहत उसकी याचिका। पी.सी. कुछ निर्देशों के साथ निस्तारण किया गया। अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में प्रतिवादी संख्या के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी। धारा 341, 342, 211 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए 4 से 6। और 7.8.2004 को हुई घटना के संबंध में नारकोटिक ड्रग्स

एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (इसके बाद "एनडीपीएस एक्ट" के रूप में संदर्भित) की धारा 58 को आईपीसी की धारा 120-बी के साथ पढ़ा जाएगा। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करने के संबंध में कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं थी, जिससे प्रथम दृष्टया यह पाया जा सके कि प्रतिवादी नं. 4 ने बदनीयती से गाड़ी रोककर तलाशी ली थी। उच्च न्यायालय ने इसे प्रतिवादी संख्या 4 के कर्तव्य के एक भाग के रूप में देखा। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा निभाई गई कथित भूमिका में भी गलती नहीं पाई। हालाँकि, अपीलकर्ता के लिए यह खुला छोड़ दिया कि वह प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के आरोप के आधार पर अपने वैकल्पिक उपचार का लाभ उठा सके कि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 जानबूझकर पुलिस को झूठी कॉल करके उसे फंसा रहे थे।

3. इसकी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि प्रतिवादी संख्या 4, 5 और 6 में से, चौथा प्रतिवादी एक पुलिस अधिकारी है जो सहायक उप-निरीक्षक, पुलिस के रूप में कार्यरत है और करनाल के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में तैनात है और वर्तमान में राम नगर, करनाल में तैनात है, जबकि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 निजी व्यक्ति हैं। अपीलकर्ता की एक बेटी है जिसका नाम निधि मागो है और वर्ष 1999 में, प्रतिवादी संख्या 6 के बेटे प्रशांत अरोड़ा के साथ उसके विवाह संबंध पर चर्चा की जा रही थी। जो उस समय भारत से बाहर था और मई, 1999 के अंत में भारत आने वाला था।

4. अपीलकर्ता के अनुसार, निधि मागो का 15.5.1999 को चंडीगढ़ से अपहरण कर लिया गया था। यह अपहरण प्रतिवादी संख्या 5 संजय भारद्वाज के कहने पर किया गया था।. कथित तौर पर उसे विवाह समारोहों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। हालाँकि, 26.5.1999 को, उसे गोलाबंदा, सी उड़ीसा से बचाया गया और अगले दिन,

धारा 376, 363, 366, 468, 467, 471 और 120-बी आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया। एफ.आई.आर. क्रमांक 0087/1999 के माध्यम से विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 5, उसके पिता और उसका दोस्त के । फिर यह तर्क दिया गया कि इस एफआईआर के लंबित रहने के दौरान, निधि मागो की शादी प्रतिवादी संख्या 6 के बेटे प्रशांत अरोड़ा से 1.6.1999 को हुई थी और विवाह पंजीकृत किया गया। वह करनाल में प्रशांत अरोड़ा के साथ रहने लगी। इसके बाद प्रशांत अरोड़ा वापस कनाडा चले गए जहां से वह आए थे और निधि मागो को भी इस आश्वासन के साथ उनके माता-पिता के घर वापस भेज दिया गया कि जैसे ही उनका वीजा मिलेगा, उन्हें कनाडा भेज दिया जाएगा। हालाँकि, यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी सं 6 ने उसका पासपोर्ट ले लिया। जून, 1999 में, कथित तौर पर, अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 6 के बीच विवाद हुआ था, कथित दहेज की मांग के कारण. इसी के आधार पर प्रतिवादी नं. 5 और 6 ने एक दूसरे के साथ मिलीभगत की और एफ अपीलकर्ता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जुलाई, 1999 के महीने में, प्रतिवादी नं 6 ने प्रशांत अरोड़ा के अटॉर्नी के रूप में शादी को रद्द करने के लिए याचिका दायर की। उसी दिन, प्रतिवादी सं 5 ने निधि मागो के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की। ये याचिकाएँ तब भी लंबित थीं जब प्रतिवादी नं. 5 ने अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध के लिए शिकायत दर्ज की, जिसे पुलिस स्टेशन, सेक्टर -17, चंडीगढ़ में एफआईआर संख्या 586/99 के रूप में दर्ज किया गया था। इसी आरोप के आधार पर मुकदमा चला. इतना ही नहीं, प्रतिवादी नं. 5 धारा 307 1.P.C के तहत आपराधिक मामला भी नालागढ़, हिमाचल प्रदेश में अपीलकर्ता और परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किया था, हालाँकि, सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 12.10.2004 द्वारा अपीलकर्ता और परिवार के सदस्यों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। साल 2001 में, निधी मागो ने प्रतिवादी संख्या 6 के बेटे प्रशांत अरोड़ा के

खिलाफ पेंडेंट लाइट के भरण-पोषण के लिए एक आवेदन दायर किया। जिस पर प्रतिवादी सं. 6 ने वह याचिका वापस ले ली जो उन्होंने अपने बेटे की ओर से दायर की थी, यह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत याचिका थी। इसके बाद, उन्होंने एक मुकदमा दायर किया, जो अभी भी लंबित है, जबकि प्रतिवादी नं. 6 का पुत्र ने अंतरिम रोक के खिलाफ एसएलपी (सी) संख्या 4708/2002 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। अपीलकर्ता के अनुसार, उक्त पुनरीक्षण याचिका अभी भी लंबित है।

5. अपीलकर्ता ने तब आरोप लगाया कि प्रतिवादी सं. 6 ने धारा 420 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए कुछ झूठे आधारों पर एक निजी शिकायत अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज की थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.1.2004 के आदेश द्वारा उसी सामान्य शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। दिनांक 21.5.2004 को अपीलकर्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री जेएस कलार चंडीगढ़ की अदालत में आया था, उक्त मामले की सुनवाई में भाग लेने के लिए, जो एफ.आई.आर. क्रमांक 586/99 के तहत दर्ज किया गया था। जब वह अदालत से बाहर आए, तो चंडीगढ़ पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों ने उन्हें और उनकी कार को घेर लिया और अपीलकर्ता को बताया कि उन्हें टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि अपीलकर्ता अपनी कार में मादक पदार्थ ले जा रहा है। कार की पूरी तरह से जांच की गई और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला और इसलिए, अपीलकर्ता और उसकी कार को छोड़ दिया गया। इस पर अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध एस.एस.पी., चंडीगढ़ के साथ शिकायत दर्ज करायी। हालांकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद, अपीलकर्ता और उसके बेटे को पंचकुला पुलिस ने फिर से उनके घर के पास से इसी आरोप में पकड़ लिया कि पुलिस के पास अपीलकर्ता के पास मादक पदार्थ ले जाने के बारे में गुप्त सूचना थी। फिर से तलाशी ली गई और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं

मिला। हालाँकि, अपीलकर्ता को रिहा कर दिया गया। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 5 के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फिर से एस.एस.पी., पंचकुला के पास शिकायत दर्ज की, जिसके लिए एफ.आई.आर. बनाया गया था। हालांकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

यह शिकायत अपीलकर्ता को झूठा फंसाने के लिए की गई थी।

6. तारीख 7.8.2004 को अपीलकर्ता और उसकी बेटी और परिवार के अन्य सदस्य अदालत में उपस्थित होने के लिए दिल्ली आए थे, जहां निधि मागो द्वारा दायर निरस्तीकरण याचिका लंबित थी। दिल्ली से करनाल वापस आते समय यह देखा गया कि उत्तरदाता 5 और 6 कार का पीछा कर रहे थे और जब वे करनाल पहुंचने वाले थे, तो उत्तरदाता 5 और 6 आगे बढ़ गए थे और उत्तरदाताओं 5 और 6 के कहने पर कार को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा लिबर्टी चौक, करनाल पर रोक दिया गया था। इसके तुरंत बाद उत्तरदाता 5 और 6 चले गए, जबकि कार की तलाशी प्रतिवादी संख्या 4 और अन्य पुलिस अधिकारियों ने ली, जिन्होंने वर्दी भी नहीं पहनी थी और न ही नेम प्लेट लगाई थी। विरोध के बावजूद कार की दोबारा तलाशी ली गई और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 4 ने अपीलकर्ता पर पुलिस स्टेशन आने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इस पर अपीलकर्ता को संदेह हुआ कि कार में कुछ रखा जा सकता है और इसलिए वह पुलिस स्टेशन जाने के बजाय, पुलिस अधीक्षक, करनाल के आवास पर गया जहां प्रतिवादी नंबर 4 भी उसके पीछे आया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दोबारा उनके आवास पर तलाशी ली गई और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। हालाँकि, यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस अधीक्षक ने प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ एक विभागीय जांच शुरू की और प्रतिवादी संख्या 4 का स्थानांतरण कर दिया गया।

अपीलकर्ता का आरोप है कि यह सब प्रतिवादी नंबर 6 के कहने पर किया गया था जो उस पर दबाव डाल रहा था।

7. अपीलकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि वह पुलिस चौकी, मॉडल टाउन, करनाल में शिकायत दर्ज कराना चाहता था, हालांकि, चूंकि प्रतिवादी नंबर 4 चौकी में सबसे वरिष्ठ अधिकारी था, इसलिए उसने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्होंने से डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने को कहा। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 4 ने शिकायत स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कोई जांच नहीं की गई। इसलिए, अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर किया। आरोप लगाया अगस्त, 2004 के महीने में उत्तरदाताओं 4, 5 और 6 के बीच अपीलकर्ता को प्रतिबंधित पदार्थ रखने के लिए झूठा फंसाकर उसके खिलाफ साजिश रची गई। इस आवेदन के पंजीकरण से पहले ही, प्रतिवादी संख्या 6 अपने वकील के साथ विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुआ और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी संख्या 6 की अनदेखी करने के बजाय अपीलकर्ता को अपना आवेदन वापस लेने का निर्देश दिया और पूरी पेपरबुक उसे वापस कर दी।

8. इसके बाद, अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आपराधिक विविध याचिका 2004 (ओ एंड एम) की संख्या 44156-एम याचिका दायर की उत्तरदाताओं 4, 5 और 6 के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58 और आईपीसी की धारा 120-बी धारा 341, 342 और 211 आईपीसी के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश के लिए। इस याचिका का प्रतिवादी संख्या 4 ने विरोध किया था, लेकिन स्वीकार किया कि लिबर्टी चौक, करनाल में तलाशी के दौरान कार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। हालाँकि, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी कार्रवाई

की दैनिक डायरी प्रविष्टि बनाई थी और इसमें कुछ भी दुर्भावनापूर्ण नहीं था। अपीलकर्ता के अनुसार, बहुत अजीब बात है कि राज्य ने प्रतिवादी संख्या 4 के उत्तर को अपनाया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 ने स्वीकार किया था कि अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कोई जांच नहीं की गई थी। संक्षेप में, अपीलकर्ता की शिकायत यह है कि उत्तरदाता 1, 2 और 3 उत्तरदाता 4, 5 और 6 के प्रभाव में शिकायत को देखने और उसे दर्ज करने का अपना वैधानिक कर्तव्य नहीं निभा रहे थे।

9. बहस के दौरान, अपीलकर्ता ने पार्टियों के बीच लंबित विभिन्न मामलों की एक सूची प्रदान की, अर्थात् एक तरफ अपीलकर्ता और दूसरी तरफ उत्तरदाता 3, 5 और 6। प्रतिवादी संख्या 6 कर्नल सदानंद अरोड़ा के संबंध में 12 मामले और प्रतिवादी संख्या 5 संजय भारद्वाज के संबंध में लगभग और 8 मामले हैं।

10. इस न्यायालय ने शुरू में विशेष अनुमति याचिका पर एक नोटिस जारी किया और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया क्योंकि अपीलकर्ता ने उसे पक्षकार बनाने के लिए याचिका दायर की थी। पक्षों को सुनने के बाद इस न्यायालय ने 27.7.2007 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

> "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रत्यारोपों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि डीजीपी की सीधी निगरानी में डीआईजी रैंक के एक अधिकारी को स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।" क्या प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने का प्रयास करके याचिकाकर्ता को परेशान करने का कोई प्रयास किया गया था। हम इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि आरोप दोनों के बीच विवादों के आलोक में लगाए गए हैं। निजी पक्ष। आमतौर पर, हम उच्च

न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हमारी राय में, इस तरह के गंभीर प्रकृति के आरोपों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। हम हरियाणा राज्य के डीजीपी से इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीनों के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध करेंगे।

तीन महीने बाद लगाओ।"

तदनुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा गहन जांच कराई गई और उनके द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है। अपने शपथपत्र में, अभिसाक्षी श्री आर.एस. दलाल, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ने सबसे पहले लिबर्टी चौक, करनाल में कार की तलाशी के संबंध में दिनांक 8.8.2004 की घटना का उल्लेख किया है और उसके बाद कहा है कि उन्होंने शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और द्वारा दिए गए बयानों का अध्ययन किया है। उनके बेटे और प्रतिवादी नंबर 4 सुरिंदर मलिक, एएसआई और पुलिस अधीक्षक, करनाल सहित 12 पुलिस अधिकारियों के बयान भी शामिल हैं। उसके बाद अभिसाक्षी ने अपना निष्कर्ष दिया। उनके हलफनामे में आगे यह सुझाव दिया गया है कि जी पुलिस अधीक्षक को गुप्त जानकारी के बारे में एएसआई के संस्करण को एसपी, करनाल श्री विकास अरोड़ा द्वारा समर्थित नहीं किया गया था और अपीलकर्ता के संस्करण को एएसआई सुरिंदर मलिक ने लेने की कोशिश की थी। गाड़ी पुलिस स्टेशन तक गई लेकिन अपीलकर्ता खुद ही सही होने के लिए एसपी के आवास पर पहुंच गया। आगे यह सुझाव दिया गया है कि यह डीडीआर संख्या 12 और 13 दिनांक 8.8.2004 से पता चला है कि खोज एसपी, करनाल के निर्देशन में नहीं की गई थी और एसपी, करनाल ने भी इस तरह की तलाशी के लिए कोई निर्देश देने से इनकार किया था। अपने हलफनामे

में डीजीपी ने श्री सुरिंदर मलिक, एएसआई और स्थानीय पुलिस के व्यवहार में गलती पाई है और कहा है कि उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है।

11. पुलिस उप महानिदेशक, राज्य अपराध शाखा, हरियाणा द्वारा दिनांक 28.10.2007 को की गई जांच रिपोर्ट की एक प्रति भी दाखिल की गई है। हम रिपोर्ट के विवरण में नहीं जायेंगे। हालाँकि, रिपोर्ट बताती है कि डीजीपी के कहने पर डीआइजी द्वारा पूरी और विस्तृत जांच की गई थी, जो जांच की प्रकृति में थी।

12. जांच रिपोर्ट देखने के बाद हम संतुष्ट हैं कि अपराध की जांच के लिए मामला है। इसलिए, हम अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत की आगे की जांच डीआइजी रैंक के अधिकारी से कराने का निर्देश देते हैं। हालाँकि, इस स्तर पर, हम इस मामले को सीबीआई को सौंपने की आवश्यकता नहीं समझते हैं क्योंकि हमारी राय में डीआईजी ने अब तक मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की है। हम उम्मीद करते हैं कि शिकायत के आधार पर उत्तरदाताओं सहित सभी संबंधित लोगों और ऐसे अन्य लोगों के खिलाफ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाएगी जिनकी दिनांक 8.8.2004 की घटना में कोई भूमिका थी। इस तरह की जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो आगे की कार्रवाई ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ की जाएगी जिनका अपीलकर्ता के उत्पीड़न में हाथ पाया गया है, जिनकी कार की लगातार तीन मौकों पर तलाशी ली गई थी और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला था। जिस DIG की देखरेख में जांच की जाएगी, वह मुकदमे के पिछले इतिहास और पिछली कार्यवाही को भी ध्यान में रखेगा और उसके लिए एक वस्तुनिष्ठ जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट उत्तरदाताओं 5 और 6 और अन्य द्वारा निभाई गई भूमिका, यदि कोई हो, के दृष्टिकोण से बात नहीं करती है। हालाँकि, उस पहलू की भी जांच की जाएगी और उस संबंध में जांच की जाएगी। हालाँकि, हम आश्वस्त हैं कि जिस स्तर पर जाँच चल रही है वहाँ कुछ भी संदिग्ध या दुर्भावनापूर्ण नहीं है और

इसलिए, हम जाँच को सीबीआई को सौंपने की अपीलकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करते हैं। हालाँकि, हम इसे स्वतंत्रता देते हैं, आवश्यकता महसूस होने पर अपीलकर्ता को दोबारा इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। हालाँकि, ऐसा तभी होगा जब जांच पूरी हो जाएगी और जांच की रिपोर्ट सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि जांच तीन महीने के भीतर पूरी हो जाएगी और यदि यह संभव नहीं है, तो जांच अधिकारी को समय के विस्तार के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी।

13. उपरोक्त निर्देशों के साथ हम वर्तमान अपील का निपटारा करते हैं।

एन.जे.

अपील निस्तारित.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक तुषार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण** : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।